सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-18 22 सितम्बर, 2015 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

केन्द्र व राज्य सरकार की आलोचना या असंतोष व्यक्त करने पर किसी को भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने का बेलगाम अधिकार पुलिस को देने वाले बीजेपी-नीत महाराष्ट्र सरकार के फासीवादी सर्कुलर का

एसयूसीआई (सी) ने किया विरोध

7 सितम्बर को जारी एक प्रेस बयान में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने कहा :

बीजेपी-नीत महाराष्ट्र सरकार द्वारा 27 अगस्त, 2015 को जारी नितांत फासीवादी सर्कुलर का हम कड़ा विरोध करते हैं जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की आलोचना या असंतोष व्यक्त करते पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ औपनिवेशिक जमाने की एक धारा, आईपीसी की धारा 124 ए लागू की जा सकती है जो ''शब्दों द्वारा, चाहे जबानी या लिखित या संकेतो या दृश्य चित्रण द्वारा हो या अन्य तरह से नफरत फैलाने या तिरस्कार, असंतोष पैदा करता है या करने का प्रयास करता है और केन्द्र या राज्य सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काता है'' उसे राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने का बेलगाम अधिकार पुलिस को दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार का यह क्रूर फरमान संविधान की धारा 14 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गारंटीशुदा मौलिक अधिकार का ही खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है।

हम तमाम सही सोच रखने वाले जनवाद पसंद नागरिकों के साथ-साथ तमाम वामपंथी और जनवादी पार्टियों का आह्वान करते हैं कि वे प्रतिवाद में उठ खड़े हों और इस लोकतंत्र-विरोधी सरकुलर को तुरंत वापस लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मजबूर कर दें।

एसयूसीआई (सी) की अपील

भारत और पाकिस्तान की मेहनतकश जनता समझ ले कि दोनों देशों के पूंजीवादी शासक लोगों के जीवन में तमाम समस्याओं की जड़ घोर पूंजीवादी शोषण से ध्यान हटाने के लिए बढ़ा रहे हैं सीमा पर तनाव

9 सितम्बर को जारी किये गये एक प्रेस बयान में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने कहा : इस बात से हम बड़े चिन्तित हैं कि जब भारत-पाक सीमा क्षेत्र, खासकर कश्मीर घाटी में आतंकी कार्रवाइयों की समस्या लगातार बनी हुई है और बढ़ रही है, तब समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों की तरफ से कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाने की बजाय सीमा पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच गोलबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए दोनों देशों की बुर्जुआ सरकारों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए तामाम कोशिशें की जा रही हैं। हम जानते हैं कि जब जीवन के तामाम तबकों में दमनात्मक पूंजीवादी उत्पीड़न के खिलाफ किसी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश के लोगों का गुस्सा और रोष बढ़ता जाता है तो युद्ध का हौवा खड़ा करके और सीमा पर तनाव बढ़ा कर दुख-तकलीफों से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ फेरने की कोशिश शासक करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के बेरहम शोषणमूलक पूंजीपति शासक भी जीवन की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसी लाइन का अनुसरण कर रहे हैं। दोनों देशों की मेहनतकश जनता के बीच मनमुटाव पैदा करने के लिए चालाकी से कोशिश कर रहे हैं और इस तरह शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था को बचा रहे हैं जो जनजीवन में तमाम दुख-तकलीफों और गरीबी, धोखाधड़ी और वंचना का मूल कारण है।

जहां तक कश्मीर का सवाल है हम निरंतर कहते आये हैं कि हालांकि कानूनी और निर्विवादित रूप से कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है फिर भी लम्बे अर्से से जिस राजनैतिक समस्या में यह उलझा हुआ है, इसको यथाशीघ्र एक सद्भावनापूर्ण माहौल में सार्थक बातचीत और चर्चा के जरिये सुलझाने की जरूरत है और इस मुद्दे पर कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। लड़ाई की मानसिकता भड़काने और युद्ध जैसे तेवर और पैंतरेबाजी अपनाने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। यह दोहराना जरूरी है कि विलय के समय कश्मीरी लोगों के अविवादित नेता शेख अब्दुल्ला के साथ किये गये समझौतों का अगर भारतीय शासकों और इसकी सरकार ने सम्मान किया होता जैसे कि राज्य के विशेष दर्जे और स्वायत्तता जो 'विलय के दस्तावेज' में संजोई गई थी, उसकी पूरी तरह से रक्षा करना, घाटी के लोगों को अपनी बेहतरीन परम्परा और संस्कृति के अनुरूप अपने राज्य का विकास करने की इजाजत देना, संघीय ढांचे की सच्ची भावना के साथ-साथ विशेष दर्जे की अभिपुष्टि के लिए भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई धारा 370 को सही मायने में बुलंद रखते हुए भारतीय गणराज्य द्वारा तमाम जरूरी मदद दी गई होती तो घाटी में इस खलबली को टाला जा सकता था, आतंकवाद की समस्या को सिर उठाते ही कुचला जा सकता था और पाकिस्तानी शासकों की इस सवाल पर कभी विक्षोभ फैलाने का मौका ही नहीं मिलता।

हम दोनों देशों के मेहनतकश अवाम का आह्वान करते हैं कि वे अपने-अपने शासकों के इस घिनौने खेल को समझें, कभी उनके अनिष्टकारी षड़यंत्र और अभिप्रेरित प्रचार का शिकार न हों, कभी ऐसी किसी बात में न उलझें जो लोगों में दरार पैदा करे जिसे उनके दमनकारी पूंजीपति शासक अपने प्रतिक्रियावादी शासन को बचाने के लिए पैदा करने पर आमादा हैं और अपने-अपने शासकों के इन तमाम घृणित षड़यंत्रों के खिलाफ जोरदार न्यायसंगत जनवादी आन्दोलनों को मजबूत करने के लिए अपनी पांतों को सुदृढ़ करें।

शिवदास घोष चिन्तन की रोशनी में विश्व साम्यवादी आन्दोलन को संशोधनवाद से मुक्त करते हुए नये तरीके से गठित करें

– गुवाहाटी की जनसभा में कॉमरेड असित भट्टाचार्य

सर्वहारा के महान नेता, इस युग के अन्यतम अग्रणी मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष की 39 वीं मृत्यु वार्षिकी पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट)पार्टी की आसाम राज्य कमेटी द्वारा 6 अगस्त को गुवाहाटी जिला लाईब्रेरी के सभागार में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता पार्टी की राज्य सचिव कॉमरेड चन्द्रलेखा दास ने की। पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड असित भट्टाचार्य सभा के मुख्य वक्ता थे। उल्लेखनीय है कि यह स्मृति सभा 5 अगस्त को होनी थी उसी अनुरूप हाल बुक किया गया था, लेकिन इस सभा को बाधित करने के लिए आसाम सरकार ने अंतिम समय में अचानक बुंकिग रद्द कर दी।

मुख्य वक्ता कॉमरेड असित भट्टाचार्य ने अपने भाषण में सभा के तात्पर्य की व्याख्या करते हुए कहा, 5 अगस्त कॉमरेड शिवदास घोष स्मृति दिवस हम हर साल मनाते हैं। इस बार भी मना रहे हैं। लेकिन इसमें औपचारिकता का कोई स्थान नहीं है। इसकी जरूरत हमारे खुद के लिए है, भारतवर्ष के शोषित जनसाधारण के जनमुक्ति संग्राम को तेजी से बढ़ाने की जो ऐतिहासिक क्रान्तिकारी जिम्मेदारी हम पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गुवाहाटी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड असित भट्टाचार्य

कॉ. असित भट्टाचार्य का भाषण ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

आयद हुई है, उसको सही तरीके से निभाने और खुद को उसके लायक बनाने के लिए इस दिन नये सिरे से हम संकल्प लेते हैं। हालांकि साल के प्रत्येक दिन ही बहस-मुबाहिसों, सभा बैठकों के माध्यम से हम यह काम करते हैं फिर भी पार्टी जीवन के सबसे दुखमय इस दिन को हम सभी और भी उन्नत क्रान्तिकारी के रूप में खुद को निर्मित करने के उद्देश्य से मिलकर संकल्पबद्ध होते हैं और जनसाधारण के सामने प्रस्तुत होते हैं जैसे कि इस कर्तव्य की अपरिहार्यता को जनसाधारण को समझा सकें।

कामरेड शिवदास घोष ही भारत की सरजमीं पर कम्युनिस्ट आन्दोलन के असल प्रतिष्ठाता थे। इसकी व्याख्या करते हुए कामरेड भट्टाचार्य ने कहा आप में से बहुत से जानते हैं कामरेड शिवदास घोष स्कूल जीवन से ही देश के स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल हो गये थे और व्यक्तिगत सबकुछ को तिलांजलि देकर पूरे मनोयोग से स्वाधीनता आन्दोलन के अन्यतम क्रान्तिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य बनकर दुर्जेय संघर्ष में लिप्त हुए थे। उस समय गांधी जी के आन्दोलन में संचालित स्वाधीनता संग्राम की समझौतावादी धारा जो देश को सर्वनाश की तरफ धकेल रही थी इसको परास्त करने, इसका मुकाबला करने की जरूरत महसूस हुई। इसी उद्देश्य से ही शुरू हुये पूरे भारतवर्ष में समझौताहीन धारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन संचालित करने के प्रयास। इस महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करने के लिए अनुशीलन समिति के अगुआ कार्यकर्ताओं को देश के विभिन्न भागों में भेजने का फैसला लिया गया। उस समय अनुशीलन समिति के जो प्रमुख नेता थे उनकी नजरों में कॉमरेड शिवदास घोष का संघर्ष आया। कॉमरेड शिवदास घोष और कॉमरेड नीहार मुखर्जी को क्रान्तिकारी आन्दोलन संगठित करने के लिए ढाका से कोलकाता भेजा गया। कुछ दिनों के अंदर ही कॉमरेड शिवदास घोष को जेल में डाल दिया गया। देश में तब उथल-पुथल का माहौल था। देश जब स्वाधीनता की दहलीज पर था तभी वे जेल से रिहा हुए। लेकिन इसी बीच गाँधी, जवाहरलाल इत्यादि समझौतावादी नेताओं के आचार-व्यवहार, चिन्तन-भावना, उनके क्रियाकलाप के संबंध में जनमानस में संशय घर कर गया था। जनसाधारण के मन में सवाल आ गया था कि गाँधीवादियों के समझौतावादी रास्ते सत्ता हस्तांतरण के माध्यम से जो स्वाधीनता हासिल होगी वह किस तरह की स्वाधीनता होगी? इस स्वाधीनता से देश के 90 प्रतिशत लोगों-शोषितों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों सभी तबकों के लोगों की शोषण से मुक्ति पाने की जो चाह है वह कितनी दूर तक पूरी होगी? जनसाधारण के मन में यही सवाल उथल-पुथल मचा रहा था लेकिन सटीक उत्तर खोजने पर भी नहीं मिल रहा था। देश में बहुत से महारथी धाकड़-धुरन्धर नेता रहने के बावजूद इस सवाल का उत्तर देने के लिए कोई आगे नहीं आया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया नाम से 20 के दशक में जो पार्टी निर्मित हुई थी वह भी अक्षम रही। यहां तक कि एम.एन.राय जैसे ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन संगठित करने का प्रयास किया था और बाद में जो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन गठित करने के प्रयास से भी जुड़े थे और लेनिन का सानिध्य भी मिला था, वे भी ठीक इसी जगह निष्फल हो गये। इसी परिस्थिति में कॉमरेड शिवदास घोष जेल से छूटे तब 17-18 साल के युवक थे, स्कूल कालेज की डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, देश के करोड़ों करोड़ शोषित लोगों की मुक्ति के सवाल के साथ पूरी तरह से एकात्म होकर आगे आये थे। मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने ही सबसे पहले स्वाधीनता आन्दोलन का चरित्र निर्धारित करके एक सुस्पष्ट विश्लेषण देश की जनता के सामने रखा और बाद के कर्तत्व के बारे में दिशा-निर्देशन दिया। सुस्पष्ट शब्दों में कॉमरेड घोष ने विश्लेषण करके दिखाया कि राष्ट्रीय पूँजीपति के साथ सांठगांठ करके समझौतावादी गाँधीवादी नेतृत्व के साथ गुप्त समझौता करके सत्ता हस्तांतरण के माध्यम से जो आजादी आ रही है उससे राजनैतिक तौर पर देश में एक परिवर्तन होगा, यह बात सही है, अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्यवादी आज शासन क्षमता में नहीं हैं, राजनैतिक तौर पर देश आजाद है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने दिखाया कि आर्थिक परिवर्तन सम्भव नहीं हुआ। शासक बदल जाने पर भी शोषण यंत्र नहीं बदला। केवल साम्राज्यवादी शोषण ही नहीं बल्कि देश के अन्दर जमींदार, जोतदार, महाजन, पूँजीपति वर्ग का शोषण-अर्थात् हर तरह के शोषण से जनता की मुक्ति की जो आकांक्षा आजादी आन्दोलन में निहित थी, गाँधीवादियों के विश्वासघात के चलते वह व्यर्थ हो गई। क्योंकि राजसत्ता चली गई उनके ही भरोसेमंद टाटा-बिड़लाओं, गोयन्काओं आदि राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के हाथों में। कॉमरेड शिवदास घोष ने आगे दिखाया कि गाँधीजी के सत्याग्रह की वजह से नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में समझौताहीन धारा का जो क्रान्तिकारी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था और गाँधीजी की समझौतावादी गलत लाइन को चैलेन्ज किया गया था, उसी के धक्के से ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर देश छोड़ कर भागने को मजबूर हुए थे। लेकिन नेतृत्व में गाँधीवादियों के रहने की वजह से आजादी का सारा फल राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग ने हड़प लिया। नतीजतन, भारत की जनता साम्राज्यवादी शोषण की जगह राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के नये शोषण की शिकार बन गई और शोषण की मात्रा आये दिन बढ़ती चली गई। इसीलिए भारत की जनता को एक और क्रान्ति का सामना करना होगा और वह क्रान्ति होगी पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति।

कॉमरेड असित भट्टाचार्य ने कहा, कॉमरेड शिवदास घोष आजादी आन्दोलन की इस त्रासदी का विश्लेषण करके ही या जनमुक्ति का रास्ता दिखा कर ही शांत नहीं बैठ गये। मार्क्सवाद ने दिखाया है कि किसी घटना की व्याख्या कर देना ही दर्शन का एकमात्र काम नहीं है, बल्कि दर्शन का असल उद्देश्य है दुनिया को बदलना। इसके लिए उपयुक्त सिद्धांत अपनाना होगा। इसी मार्क्सवादी चिन्तनधारा में कॉमरेड शिवदास घोष ने उस सिद्धांत को जन्म देकर जनता की मुक्ति का हथियार सही क्रान्तिकारी पार्टी बनाने का एक असाधारण, कल्पनातीत संग्राम भी छेड़ दिया था। अर्थात् देश के 90 प्रतिशत शोषित लोगों की हर तरह के शोषण से मुक्ति का लक्ष्य सामने रखकर यह संग्राम कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा शुरू किया गया। कॉमरेड शिवदास घोष ने विश्लेषण करके दिखाया कि अनुशीलन समिति द्वारा आजादी के लिए समझौताहीन संघर्ष किये जाने के बावजूद यह मार्क्सवादी पार्टी नहीं बन पायी। क्योंकि पार्टी में मार्क्सवादी आदर्श नदारद था और सर्वहारा वर्ग दृष्टिकोण से भी यह पार्टी संचालित नहीं थी। इसके अलावा, 20 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (सीपीआई) नाम से जो पार्टी निर्मित हुई थी वह पार्टी गठन की लेनिनीय नीति व पद्धति का अनुसरण न कर पाने की वजह से सही कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में गठित नहीं हो सकी। लेनिन की सीख है, सही क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व के बिना किसी भी देश में क्रान्ति नहीं हो सकती और सही क्रान्तिकारी सिद्धांत के बिना सही क्रान्तिकारी पार्टी बनाना असम्भव है। इसलिए सही क्रान्तिकारी पार्टी देश में नहीं है और वह बनानी होगी-यही थी कॉमरेड शिवदास घोष की दृढ़ घोषणा।

जब उन्होंने यह बात कही थी, तब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन का गौरवमय समय 1945-46 साल था। देश-देश में समाजवादी आन्दोलन की असाधारण अग्रगति, फासिस्ट हिटलर की करारी हार इत्यादी घटनाओं से न केवल मजदूर-किसानों में बल्कि भारत और दुनिया की पूरी मेहनतकश जनता के बीच कम्युनिज्म के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा हुआ था। इसी वजह से भारत में भी सीपीआई के प्रति तब लोगों का भारी समर्थन था। इसी तरह की एक परिस्थिति में गंभीर तत्वज्ञान और संघर्ष के बीच से असाधारण शक्ति के अधिकारी कॉमरेड शिवदास घोष जो बिल्कुल अकेले थे-कोई भी समर्थक नहीं था, कोई भी पहचान नहीं थी, पत्र-पत्रिकाओं का कोई समर्थन नहीं था-फिर भी मजबूती के साथ उन्होंने यह बात कही थी कि सीपीआई असल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। उस समय यह काम कितना कठिन था इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लगभग अकेले कॉमरेड शिवदास घोष थे और चारों तरफ थी अनगिनत बाधाएं। उनका विज्ञानसम्मत विश्लेषण सुनकर अविभक्त सीपीआई लाल-पीली हो गई लेकिन कॉमरेड शिवदास घोष के धारदार तर्क का मुकाबला नहीं कर पायी। कॉमरेड शिवदास घोष ने बाहर के भयंकर विरोध, व्यंग-विद्रुप, गाली-गलौज, सब कुछ को झेलते हुए निर्वैयक्तिक रवैया अपना कर केवल आदर्श और सत्य की चर्चा के द्वारा ही लगभग असम्भव को सम्भव कर दिखाया। 1948 में एक कन्वेन्शन के माध्यम से एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) का जन्म हुआ। कॉमरेड शिवदास घोष के कष्टसाध्य संघर्ष को जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है वे ही इसे महसूस कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स अकेले केवल सत्य चर्चा, आदर्श चर्चा के संघर्ष के माध्यम से जिस तरह दुनिया के सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के रास्ते के पथप्रदर्शक बने थे, उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत का आह्वान इंग्लैण्ड और जर्मनी की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में पहुँच गया था, कॉमरेड शिवदास घोष भी केवल इसी रास्ते ही सत्य चर्चा के बल पर भारत में क्रान्तिकारी सिद्धांत को जन्म देकर सर्वहारा वर्ग के सामने मुक्ति के प्रतीक बन कर उभरे। क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) को निर्मित करते समय अमूर्त सिद्धांत को उन्होंने मूर्त रूप दिया। पार्टी निर्माण की तैयारी में अति कठिन और कठोर संघर्ष करते हुए धारदार तर्क के माध्यम से एक-एक आदमी को समझाते हुए कार्यकर्ता जुटाए थे। यहाँ तक कि अविभाजित सीपीआई में से भी कार्यकर्ताओं को आकर्षित किया था और पार्टी में शामिल कराया था। इसी अदमनीय संघर्ष के नतीजतन सर्वहारा वर्ग ने पाई अपनी खुद की पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट)। इसके बाद के समय में अबाध गति से पार्टी का विस्तार हुआ, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में लगातार पार्टी की ताकत बढ़ी, पार्टी के नेतृत्व में एक के बाद एक आन्दोलन हुआ, सब मिला कर पूरे भारत में आज पार्टी शोषित जनता की अपनी पार्टी बन गई है।

कॉमरेड भट्टाचार्य ने दृढ़ता के साथ कहा कि भारत की सरजमीं पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद को विशेषीकृत करने के जरिये कॉमरेड शिवदास घोष इस देश में असल कम्युनिस्ट आन्दोलन के प्रतिष्ठाता के रूप में उभरे हैं। साथ ही साथ तभी से कमी-खामियों से मुक्त करके विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन को शक्तिशाली करने में भी कॉमरेड शिवदास घोष ने योगदान किया था। स्टालिन अपने जीवन के अंतिम पहर तक मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन से शिक्षा लेकर उनके छात्र के रूप में मार्क्सवाद को और भी उन्नत कर गये हैं, जिसे आज मार्क्सवाद-लेनिनवाद के रूप में जाना जाता है। कॉमरेड शिवदास घोष ने भी ठीक इसी तरह मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ त्से तुंग से जो लेना था, वह लेकर अति उन्नत रूप में रोजमर्रा के जीवन संघर्ष के माध्यम से मार्क्सवाद के ज्ञान भण्डार को और भी समृद्ध, और भी विकसित किया है। यही इतिहास है। यह कार्य करने के लिए किस तरह की सैद्धांतिक शक्ति अर्जित करने की जरूरत पड़ी थी, उसको समझने की जरूरत है। मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा, ज्ञान चर्चा और जीवन में उसका प्रयोग करना और सही रास्ते से बदली हुई परिस्थिति का मुकाबला करना-यह एक जबरदस्त संघर्ष है। कॉमरेड शिवदास घोष ने देखा कि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक चिन्तन प्रक्रिया कुछ हदतक क्षयग्रस्त हुई है। कहीं भी कोई बिन्दु रहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दो में विश्व के सर्वहारा वर्ग के सामने उसे रखा। उन्होंने कहा कि कमी-खामियों को दूर करने के लिए हमें भी यथायोग्य जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि इसके बाहर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सैद्धांतिक हथियार को उपयुक्त बनाने के जरिए ही शोषणमुक्त समाज निर्माण करना सम्भव होगा। दूसरी तरफ स्तालिन की मृत्यु के बाद विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में एक

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बिहार में वाम दलों का जन राजनैतिक कन्वेंशन

पटना में वाम दलों द्वारा आयोजित जन राजनैतिक कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड छाया मुखर्जी

पटना (बिहार) : बिहार में कार्यरत छह वामपंथी दलों-एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई(एम-एल) लिबरेशन, अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक तथा आरएसपी-द्वारा गठित संयुक्त वाम ब्लॉक के तत्वावधान में यहां श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 7 सितम्बर को जन राजनीतिक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) समेत अन्य वामपंथी दलों के नेता-कार्यकर्ता सुबह से ही हॉल में जगह लेने लगे। हॉल खचाखच भर जाने पर हजारों लोग बाहर लगे प्रोजेक्टर के जरिये अंदर की कार्रवाई को देखने-सुनने में तल्लीन हो गये।

जन राजनैतिक कन्वेंशन को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) केन्द्रीय कमिटी सदस्य कॉ. छाया मुखर्जी ने कहा कि यह काफी खुशी की बात है कि आज जन जीवन के ज्वलंत सवालों पर आंदोलन और संघर्ष विकसित करने के क्रम में छह वामपंथी पार्टियां एकजुट हुई हैं। चुनाव में भी जनवादी चिंतन के आधार पर, क्रांतिकारी चिंतन के आधार पर जनता को साथ लेकर चलना होगा, उसे सही दिशा देनी होगी। देश में फासीवाद लाने की कोशिश हो रही है। अगर हम जनता को सचेत न करें, संगठित न करें तो फासीवाद को हम शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए फासीवाद को रोकने के लिए आज तमाम वामपंथी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है, वाम मोर्चे की जरूरत है। चुनाव तो जरूरी है ही, पर फासीवाद को रोकना चुनाव से भी ज्यादा जरूरी है। मोदी सरकार शिक्षा में तमाम पुराने चिंतन, कुसंस्कार ला रही है। वैज्ञानिक और तार्किक मानसिकता को खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार पूंजीपतियों को खुश करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। उसने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की। लेकिन देश की जनता ने उसका जबर्दस्त विरोध किया, संघर्ष हुए। अंततः सरकार उसे लागू नहीं कर पायी। श्रम कानूनों में पूंजीपतिपक्षीय सुधार लाकर मजदूर-कर्मचारियों के जीवन को बदहाली के गर्त्त में धकेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश का मजदूर वर्ग संघर्ष पथ पर बढ़ता जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकारों की धमकियों के बावजूद 2 सितम्बर की आम हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। देश में पूंजीपतियों ने जनता के मन में नरेन्द्र मोदी के प्रति मोह पैदा किया। नरेन्द्र मोदी जी जनता को सपने दिखा रहे थे कि वे देश में स्वर्ग ला देंगे, लेकिन जनता ने देखा कि एक साल बीत जाने के बाद भी उनके सपने हकीकत में तब्दील नहीं हुए। लोगों ने महसूस किया कि जनजीवन की एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। महंगाई आसमान छू रही है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। किसान-मजदूरों के जीवन की समस्याएं घनीभूत हो रही हैं। शिक्षा पर हमले दिनों-दिन बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर अपराध की घटनाओं में इजाफा जारी है। मोदी जी ने कहा है कि बिहार की जनता के डीएनए में जात-पांत है। यह प्रदेश की जनता के लिए कितने अपमान की बात है। किसी भी प्रदेश की जनता के डीएनए में जात-पांत नहीं होता है। जात-पांत की मानसिकता तो भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू इत्यादि पूंजीपति वर्ग की पार्टियां जनता को बांटने के लिए पैदा करती हैं। वे चुनावी वैतरणी पार करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। सालों से जनता को इसमें फंसाया जा रहा है। पार्टियों की नीति पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। जन जीवन की समस्याओं का समाधान जाति के आधार पर नहीं हो सकता। समाधान होगा जन आंदोलन के जरिये, मेहनतकश जनता के एकताबद्ध संघर्ष के जरिये। हम देख रहे हैं कि देश की सत्ता पर आबादी के मुट्ठीभर लोग मालिक-पूंजीपति काबिज हैं। देश की तमाम सम्पदा के मालिक भी वही हैं। दूसरी तरफ देश का बहुसंख्यक अवाम मेहनतकश वर्ग शोषित हो रहा है, वह अपने सारे अधिकारों से वंचित है। जब ये शोषित-पीड़ित लोग, मेहनतकश लोग सचेत हो जायेंगे, संगठित हो जायेंगे, तो वे शोषण पर आधारित इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर समाजवादी समाज कायम करेंगे। उस समाज में कोई ऊंच-नीच नहीं होगा, शोषण-जुल्म नहीं होगा। सबको भोजन मिलेगा। सबको काम मिलेगा। सबके सिर छिपाने के लिए छत होगी। इस नये समाज के निर्माण के लिए जब तक संघर्ष की जरूरत होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें केवल चुनाव तक ही सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। चुनाव के प्रति एक क्रांतिकारी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी का दृष्टिकोण बुर्जुआ वर्ग, पेटी बुर्जुआ वर्ग की पार्टियों से बिल्कुल पृथक होता है। जब तक जनता में चुनाव के प्रति मोह बरकरार रहता है, तब तक एक क्रांतिकारी पार्टी जनता को चुनाव के मोह से मुक्त करने के लिए चुनाव में भाग लेती रहती है। जब तक जनता संगठित नहीं हुई है, जब तक क्रांति की चोट से इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक जनता के साथ रहने के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी को चुनाव में भाग लेते रहना पड़ता है। चुनाव में जीत हासिल करने पर एक क्रांतिकारी पार्टी का काम होगा कि सदन में जनता के मुद्दों को उठाना, उसे जहां तक संभव हो सके राहत देना, सरकार की जनविरोधी नीतियों का जमकर विरोध करना और साथ ही सदन के बाहर क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर ताकतवर जन आंदोलन का निर्माण करना। इसी उद्देश्य को सामने रखकर एक क्रांतिकारी पार्टी को चुनाव में भाग लेना चाहिए। देश में सब कुछ है, काफी सम्पदा है, लेकिन वह सब कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चला जा रहा है। इसलिए जनता तमाम सम्पदाओं से वंचित है। वह भूखी-नंगी है। देश के 77 प्रतिशत लोगों की दैनिक आमदनी 20 रुपये है। एक तरफ देश के गोदामों में चावल-गेहूं सड़ते हैं, तो दूसरी तरफ लोग भूखों मरते हैं। यह हालात बदलनी चाहिए। वामपंथी पार्टियों का काम है इस हालात को बदलना, सही मायने में परिवर्तन लाना यानी क्रांति करना। अंत में उन्होंने प्रदेश की जनता से संयुक्त वाम ब्लॉक के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की।

जन राजनीतिक कन्वेंशन को सीपीआई के पूर्व महासचिव कॉ. ए. बी. बर्द्धन, सीपीआई (एम) के महासचिव कॉ. सीताराम येचुरी, सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन के महासचिव कॉ. दीपंकर चट्टाचार्य, आरएसपी के महासचिव कॉ. अवनी राय तथा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कॉ. देवव्रत विश्वास ने भी संबोधित किया। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अरूण कुमार सिंह समेत छह वामपंथी दलों के राज्यस्तरीय नेताओं ने भी कन्वेंशन को संबोधित किया।

राज्य के विभिन्न जिलों से आये वाम दलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने काफी जोश और उत्साह के साथ नेताओं को सुना और आगे के कार्यभार को मुकम्मल तौर पर पूरा करने के संकल्प के साथ विदा हुए।

धौलेड़ा हादसे में मारे गये निर्माण कर्मियों के परिजनों को मिले सरकारी नौकरी

नारनौल (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के बैनर तले 13 सितम्बर को स्थानीय सुभाष पार्क में निर्माण कर्मियों की जिला प्रधान सीताराम की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें सैकड़ों मिस्त्रियों और मजदूरों ने भाग लिया। प्रधान ने बताया कि गत 7 अगस्त को धौलेड़ा-बीगोपूर में नवनिर्माण हो रहे क्रेशर की दीवार ढहने से हुए हादसे में मारे गये 11 मजदूरों के परिजनों और 13 घायल मजदूरों को इन्साफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन और मालिक ने घायलों की भी सुध नहीं ली और प्राथमिक मुआवजा ही दिया गया है। घायलों को हस्पताल से शीघ्र छुटी देकर घर भेज दिया गया जहां वे झुग्गी-झोंपड़ियों में असहाय हालत में पड़े कराह रहे हैं। पीड़ित श्रमिकों के शरीर पर घाव हैं, किसी की हड्डियां टूटी हुई हैं। वे ठीक से खाना नहीं खा सकते हैं और न ही शौच जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें हस्पताल से छुट्टी कैसे दे दी गई। यूनियन ने नारनौल सामान्य हस्पताल में इन घायलों को दाखिल कर पूरा इलाज कराने और सभी मृतकों व घायलों को पंजीकृत मान कर उनके परिवारों को बाकी बचा मुआवजा शीघ्र दिलाया जाने और मृतकों के हर आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाने की मांग की।

बैठक के बाद यूनियन के सभी सदस्य वहां से जुलूस की शक्ल में शहर में प्रदर्शन करते हुए लघुसचिवालय पहुंचे और वहां उन्होंने नायब तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एआईयूटीयूसी के प्रांतीय अध्यक्ष कॉ. सत्यवान, यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉ. धर्मवीर सिंह, प्रदेश सचिव कॉ. बलराम यादव, बलबीर सिंह, मास्टर सूबे सिंह, कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने सम्बोधित किया। ओमप्रकाश, थावर सिंह, बाबूलाल, गुरप्रीत कौर, संतोष, सुनीता, लीला राम, शेर सिंह, अंगनाराम, सुभाष, कर्णसिंह आदि भी मौजूद थे।

नारनौल में मांगों के लिए प्रदर्शन करते निर्माण श्रमिक

साइन्स कॉलेज छात्र सम्मेलन सम्पन्न

दुर्ग (छ.ग.) : 11 सितम्बर को ऑल इंडिया डेमाक्रेटिक स्टूडेन्ट्स आर्गेनाइजेशन की ओर से साइन्स कॉलेज छात्र सम्मेलन स्थानीय मालवीय पार्क में सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। छात्र सम्मेलन की शुरूआत आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजली देते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर व क्रांतिकारी गीतों से हुआ। तत्पश्चात् शुभम पांडे द्वारा मूल प्रस्ताव पढ़ा गया जिसके समर्थन में प्रवीण शर्मा ने विस्तार से बात रखी। सम्मेलन में उपस्थित कई छात्र-छात्राओं ने भी इस पर चर्चा की। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ए.आई.डी.एस.ओ. साइन्स कॉलेज कमेटी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष-प्रवीण शर्मा, उपाध्यक्ष- पूजा सागर, सुनीता कुमारी, किशन मारकण्डे, मेनका निषाद, सचिव-शुभम पांडे, सहसचिव-दिव्या निषाद, कोमल यादव, दीपा कौशल, शीतल सेन, बलराम देवांगन, रेवती निषाद कार्यकारिणी सदस्य-दीपा मेहरा, गायत्री साहू, पूजा बोरकर, पदमा पाटिल, गिरीश साहू, पूनम यादव, खेमीन साहू, भूपेन्द्र कुमार, झीमत साहू, शशिकिरण, सुमन विश्वकर्मा चुने गये।

मुख्य वक्ता एआईडीएसओ, छत्तीसगढ़ राज्य संयोजक आत्मा राम साहू ने छात्रों को सम्बोधित किया। मुख्य अतिथि एआईडीएसओ के पूर्व संयोजक कॉ. विश्वजीत हारोडे ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। अंत में कॉलेज की समस्याओं को लेकर भावी आन्दोलन की रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूनेश्वरी साहू ने की और संचालन नीतू कुमारी द्वारा किया गया।

कॉ. असित भट्टाचार्य का भाषण ...

(पृष्ठ 2 का शेष)

अकल्पनीय परिस्थिति पैदा हो गई। आधुनिक संशोधनवाद ने घातक रूप से सिर उठाया। उल्लेखनीय है कि कुछ अलग तरह के संशोधनवाद का लेनिन को भी मुकाबला करना पड़ा था। कम्युनिस्ट नाम इस्तेमाल करते हुए ही, कम्युनिस्ट नाम का जामा पहनकर बर्नस्टीन, काउत्सकी इत्यादि नेतागण पूँजीवादी चिंतन के धारक-वाहक बन गये थे। चुनावों के जरिये जनता की मौलिक समस्याएं दूर करना संभव होगा, इसी रास्ते से क्रान्ति संभव होगी ये बातें बोल कर उन्होंने जनता को चुनावी मकड़जाल की तरफ धकेल देना चाहा था। इसे लेकर दूसरे इंटरनेशनल में जबरदस्त मतभेद उभर कर सामने आये थे। लेनिन ने अकेले खड़े होकर इसके विरूद्ध संघर्ष किया था। फिर स्तालिन की मृत्यु के बाद ही विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के अंदर से ही इस तरह के निकृष्ट बुर्जुआ चिंतन ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। पूँजीवादी देशों में पूँजीपतियों ने जनता का शोषण करने के लिए उसे अचेतन अवस्था में रखने का जो षड़यंत्रकारी जाल बुना था, चुनाव उसका ही एक उपाय मात्र है। इसी तरह ही ख्रुश्चेव, ब्रिजनेव से शुरू कर गोर्बाचेव आदि तक सभी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रत्येक स्तर पर पूँजीवादी चिंतन भावना समाज में चालू करते रहे। उसके परिणाम स्वरूप ही सोवियत यूनियन सहित पूर्वी यूरोप के देशों में पूँजीवाद पुनः स्थापित होने की जमीन तैयार हो गई थी।

कॉमरेड घोष ने और भी दिखाया कि एक विशेष तरह का व्यक्तिवाद, उनके शब्दों में 'समाजवादी व्यक्तिवाद' और उसके साथ एक विशेष तरह के अर्थवाद, नये अर्थवाद ने समाजवादी देशों में सिर उठाना शुरू कर दिया, सारे समाज को अच्छादित कर दिया था। कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया कि इन दोनों की जड़ व्यक्तिगत सम्पत्तिबोध के अंदर निहित है। उन सब के जरिये निकृष्ट पूँजीवादी चिंतन सोवियत यूनियन को चुनौती देने लायक शक्ति संचित कर सका। उत्पादन की बहुतायत का धुंआ उठाकर खुश्चेव आदि ने नया अर्थवाद–अर्थात् मैं काम करूंगा लेकिन ज्यादा वेतन चाहिये, इस तरह के इन्सेटिव सिद्धान्त को लाकर समाजवाद को खतरे में डाल दिया। इसी तरह आधुनिक संशोधनवाद के चंगुल में फंसकर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की कमर टूट गई। कम्युनिस्ट आन्दोलन के शत्रु आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ माओ त्से-तुंग ने महान सांस्कृतिक क्रान्ति की शुरूआत की थी ताकि चीन में यह संक्रमण न घट सके। लेकिन अंत तक रक्षा नहीं हो सकी, माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद चीन में भी प्रतिक्रान्ति हो गई।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में अति विनाशकारी इस संशोधनवाद के उत्थान के मूल कारण की व्याख्या करते हुए कामरेड शिवदास घोष ने दिखाया कि स्तालिन के नेतृत्व में समाजवादी रूस के भौतिक विकास (आर्थिक-सामाजिक-साँस्कृतिक विकास) ने पूरी दूनिया को अचंभित कर दिया था, पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देश उसके आगे नतमस्तक होने को मजबूर हुए थे। लेकिन स्टालिन की मृत्यु के बाद, यहां तक कि स्तालिन के समय में भी, आदर्शगत सैद्धान्तिक चर्चा का स्तर जितना ऊँचा उठाने की जरूरत थी उतना वह हुआ नहीं। साम्यवादी आन्दोलन में संशोधनवाद के उत्थान को कॉमरेड शिवदास घोष ने अपने शब्दों में *इंफिल्ट्रेशन ऑफ बुर्जुआ थोट्स एण्ड आइडियाज इन द कम्युनिस्ट मूवमेंट एण्ड इन द सोशलिस्ट स्टेट्स* (साम्यवादी आन्दोलन और समाजवादी राष्ट्रों में बुर्जुआ चिंतन भावना की घुसपैंठ) बताते हुए चिन्हित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कम्युनिस्ट चेतना का सापेक्ष रूप में निम्न स्तर ही आधुनिक संशोधनवाद के आर्विभाव का मूल कारण है।

आधुनिक संशोधनवाद को निर्मूल करके विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन को पुनर्जीवित करने का पथ निर्देश करते हुए जो सिद्धान्त कामरेड शिवदास घोष ने प्रस्तुत किया था उसकी व्याख्या करते हुए कामरेड असित भट्टाचार्य ने कहा, आधुनिक संशोधनवाद का प्रतिरोधक है कम्युनिस्ट चेतना के मान को प्रतिदिन उन्नत स्तर पर ले जाना। सिद्धान्त का निरंतर विकास करते हुए और भी उन्नत स्तर पर नहीं ले जा पाने से इसका प्रतिरोध करना संभव नहीं होगा। 40 वर्ष पहले की एंटीबायोटिक जिस तरह आज की जरूरत को ठीक पूरा नहीं कर सकती, और भी उन्नत एंटी-बायोटिक की जरूरत होती है, उसी तरह अतीत के सिद्धान्त को उन्नततर स्तर पर ले जाना, उसको और भी धारदार करना महत्वपूर्ण जरूरत हैं। इसी क्षेत्र में कामरेड शिवदास घोष का योगदान उनके जीवन की एक महान कीर्ती है। आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन को इसके चंगुल से मुक्त करने के लिए कामरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि किस तरह और क्यों बुर्जुआ मानवतावादी चिंतन जड़ और निशेषित हो गया है। मानवतावादी चिंतन पूँजीवाद के विकास के साथ आया था। सभ्यता की प्रगति में उस समय इसका प्रभाव अतुलनीय था। इसी वजह से सामाजिक स्वार्थ को व्यक्ति स्वार्थ के उपर स्थान दे सकना ही था उस समय कम्युनिस्ट चेतना का स्तर निर्धारित करने का मापदण्ड। लेकिन आज पूँजीवाद के इस ह्रासोन्मुख युग में, आधुनिक संशोधनवाद की जब धारा बह रही है, तब वह चिन्तन काम नहीं करेगा। आज के समय में कम्युनिस्ट चेतना का न्यूनतम मान है व्यक्ति स्वार्थ को सामाजिक स्वार्थ के साथ एकात्म कर पाना, दकदम विलीन कर देना। कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति इस चिन्तन के नजदीक पहुँच कर भी उसको सैद्धांतिक स्वरूप नहीं दे सकी। कॉमरेड शिवदास घोष चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति का अभिनन्दन करते हुए इसे शानदार बताते हुए उसकी सीमाबद्धता के इस पहलू का भी उल्लेख कर गए हैं। व्यक्ति स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ एक तथा अभिन्न है, समाज मरेगा तो व्यक्ति करेगा, समाज बचेगा तो व्यक्ति भी बचेगा, इसे विज्ञान के सिद्धान्त की तरह ही प्रत्येक कम्युनिस्ट को समझना होगा। व्यक्तिवाद से मुक्त होकर सामाजिक स्वार्थ के साथ एकात्मीकरण के मूर्त प्रतीक के रूप में खुद को ढालना होगा। आज के समय संघर्ष की मूल जगह यही है।

कॉमरेड शिवदास घोष के जीवन संघर्ष और शिक्षा के दूसरे पहलुओं का उल्लेख करते हुए कॉमरेड भट्टाचार्य ने कहा समय के बदलाव के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद को और भी समृद्ध, उन्नत और विकसित करने के रास्ते और भारत की सरजमीं पर उसको विशेषीकृत रूप देकर असल कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापित करते हुए मार्क्सवाद के ज्ञान भण्डार में कॉमरेड घोष का जो सब सैद्धांतिक योगदान समझ सकें तो यह महासागर की तरह है। देखा जा रहा है कॉमरेड शिवदास घोष की इन शिक्षाओं को जहाँ जितनी हद तक हम ले जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि देश के बाहर भी, इसके जरिए कम्युनिस्ट आन्दोलन को दिशा मिल रही है। उनका चिन्तन लोगों को चुम्बक की तरह आकर्षित कर रहा है। विभिन्न देशों में कॉमरेड घोष के चिन्तन के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी निर्मित हुई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण के क्षेत्र में कॉमरेड शिवदास घोष ने लेनिन की शिक्षा को ऊँचा उठाते हुए उसको और भी समृद्ध किया है और विशेषीकृत किया है और अन्यान्य मार्क्सवादी ऑथोरिटियों के चिन्तन को विकसित किया है और इसी रास्ते उनका भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद की एक ऑथोरिटी के रूप में आविर्भाव हुआ है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षा एक अति शक्तिशाली अपराजेय हथियार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में आधुनिक संशोधनवाद को जड़ से क्यों नहीं उखाड़ फेंका जा सका–एक और पहलू से प्रश्न को इस तरह भी प्रस्तुत किया जाए कि किस तरह, किस रास्ते, किस सिद्धान्त से संचालित होकर इसे जड़ से उखाड़ फेंकना संभव होगा? यहाँ पर कॉमरेड शिवदास घोष की इस सम्बंध में अमोघ शिक्षा की समझ और प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। पूरी दुनिया के बहुंत से देशों में कम्युनिस्ट नाम का तमगा लगा कर भयंकर आधुनिक संशोधनवाद सर्वव्याप्त हो कर कायम है। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन को आधुनिक संशोधनवाद के चंगुल से मुक्त करना होगा। इसके लिए कम्युनिस्ट चिन्तन भावना के स्तर को ऊँचा उठाना होगा, जिसका आधार होगा कॉमरेड शिवदास घोष की इस सम्बंध में अत्यंत मूल्यवान शिक्षा–सामाजिक स्वार्थ और व्यक्ति स्वार्थ पूरी तरह एकात्म होने का क्षेत्र तैयार करने के माध्यम से, समाजवादी व्यक्तिवाद, जिसका स्रोत है व्यक्तिगत सम्पत्तिबोध, उसको और नए अर्थवाद या पूँजीवादी देशों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के माध्यम से जो निकृष्ट अर्थवाद का अभ्यास चल रहा है–इन सबको निर्मूल करने के जरिए प्रत्येक देश में असल कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्मित करने को सार्थक करने के माध्यम से।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है उनके हाथों से निर्मित एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) उसके सिद्धान्तों को आधार बनाकर विभिन्न राज्यों में शक्तिशाली हो रही है यह पूरी तरह सटीक होने के बावजूद जरूरत के मुताबिक हमारी अग्रगति में स्थिलता का कारण क्या है? भारत में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) जनतांत्रिक आन्दोलन करते करते ही जो शक्ति लेकर नेतृत्व की जगह पहुँच जाने की बात थी, उसकी गति बहुत धीमी है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। चारों तरफ पार्टी का सुनाम है। जनसाधारण चाहते हैं पार्टी का तेजी से विकास हो। आज की सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल), नक्सल इत्यादि पार्टियों के बारे में लोगों की धारणा काफी हद तक साफ हो गई है। इस पहलू से विचार करने पर बाहर का अवरोध आज इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पूँजीवाद को छोड़कर असल में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। कोई अवरोध नहीं। तब तेजी से विकास के मामले में समस्या कहाँ है? इसी को आज कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के आधार पर निर्धारित करना होगा। हर किसी को खुद से प्रश्न करना होगा, खुद का व्यक्तिगत सब कुछ स्वेच्छा से विसर्जित करके व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत सम्पत्ति जनित मानसिकता से मुक्त होने के संघर्ष के रास्ते खुद को असल कम्युनिस्ट के रूप में एक मॉडल कैरेक्टर के रूप में ढालने का जो निहायत जरूरी संघर्ष, जिसकी पद्धति, तमाम बारीक पहलू कॉमरेड घोष निर्धारित कर गए हैं, यह सब ठीक तरह से हो रहा है क्या? तब तो समस्या यहीं पर है। रुकावट बाहर की नहीं हमारे अन्दर की है। हम ही अपने विकास को अवरुद्ध कर दे रहे हैं। महान कार्ल मार्क्स ने कहा था, 'कम्युनिज़्म इज़ ह्युमनिज़्म माइनस प्राईवेट प्रोपर्टी' (साम्यवाद है व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्तिबोध से रहित मानवतावाद)। इसीलिए देखिए कम्युनिस्ट चरित्र हासिल करने के मामले में कार्ल मार्क्स ने किस बिन्दु पर जोर दिया था? व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्तिबोध से पूरी तरह मुक्त होना ही कम्युनिस्ट होने के मामले में निर्णायक है। इस बात को ठीक तरह से ना समझ पाने से सत्य उद्घाटित नहीं होगा। हम सत्य से बहुत दूर पीछे रह जाएंगे। शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास 'श्रीकांत' में कहा है–निस्वार्थ जीवन से ही सत्य उपलब्धि कर पाता है। इस सवाल पर कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षा हैं–क्रान्तिकारी को सभी सवालों पर, यहाँ तक कि यौन जीवन के सवाल पर भी सम्पूर्ण निर्लोभ और निस्वार्थ होना होगा। और भी बताया है त्याग की अग्नि में तप कर क्रान्तिकारी चरित्र निर्मित करना होगा। और यह भी याद दिलाते हुए कहा था असल मायने में यह त्याग नहीं है। कुटिया छोड कर अट्टालिका में जाना त्याग नहीं है। त्याग कर रहा हूँ ऐसा सोचने से तो अहंकार और आत्म संतुष्टि पैदा होती है। पार्टी के लिए कितना कुछ किया, छोड़ दिया– ये सब सोच तो व्यक्तिवाद की ठोस अभिव्यक्ति है, इस सब भावनाओं से मुक्त न होने से हमारी कम्युनिस्ट चेतना जितनी दूर तक उन्नत हुई थी वह भी नहीं रहेगी। तो फिर इन सब मानसिकताओं के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष खुद को ही करना होगा और इसका अमोघ हथियार है उपयुक्त सैद्धांतिक चर्चा अभ्यास।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सीकर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का विरोध

पिलानी में जुलूस निकालते हुए छात्र-नौजवान

जयपुर में जुलूस निकालते हुए छात्र-नौजवान व महिलाएं

पिलानी (राजस्थान) : सीकर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की लापरवाही के विरोध में 13 सितम्बर को ऑल इण्डिया डीएसओ-ऑल इण्डिया डीवाईओ द्वारा संयुक्त रूप से पिलानी बंद का आह्वान किया गया। डीवाईओ के राज्य सचिव कॉ. शंकर दहिया के नेतृत्व में छात्र-नौजवानों ने पिलानी में जुलूस निकाला।

डीवाईओ-डीएसओ ने मांग की कि महिलाओं पर बढ़ते अपराध की रोकथाम की जाए, बलात्कार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, शराब बिक्री पर रोक लगाई जाए, प्रचार माध्यमों से अश्लीलता फैलाना बंद किया जाए। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे और हाथों में मांग पट्टिकाएं थामे हुए थे। जुलूस निहाली चौक, बड़ चौक, बस स्टैण्ड, राजगढ़ रोड़ होते हुए मुख्य बाजार में पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। इस जघन्य घटना की निंदा करते हुए कॉ. शंकर दहिया ने कहा कि महिलाओं, खास कर मासूमों पर बढ़ते अत्याचार गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने इनकी रोकथाम हेतु आगे आने के लिए लोगों का आह्वान किया। सभा को विष्णु शर्मा, राजू सिहाग, डा. रविकांत ने भी सम्बोधित किया।

इस मौके पर अर्जुन लाल, भूवनेश्वर, कृष्ण कुमार, प्रियदर्शन, अशोक, कार्तिक, प्रमोद सैनी आदि मौजूद थे।

इस दिन पिलानी में ज्यादातर जगह दुकाने बंद रख कर लोगों ने इस घटना का विरोध किया।

जयपुर : सीकर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ 17 सितम्बर को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इण्डिया डीएसओ और ऑल इण्डिया डीवाईओ की ओर से बाईस गोदाम पुलिया से विधानसभा तक संयुक्त जुलूस निकाला गया।

आंगनवाड़ी कर्मियों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

रोहतक में लघुसचिवालय पर प्रदर्शन करती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं

रोहतक (हरियाणा) : 10 सितम्बर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन हरियाणा रजि. नं. 1996 की रोहतक जिला कमेटी ने शहर में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और विभागीय जिला अधिकारी रोहतक तथा उपायुक्त रोहतक को अपने मांग पत्र दिये। यूनियन की महासचिव पुष्पा दलाल, जिला प्रधान रोशनी चौधरी, जिला सचिव सुनिता देवी के नेतृत्व में जिला भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले छोटूराम पार्क में इकट्ठी हुई और सभा की। उनके अलावा कौशल्या, तसवीर, सरोज, धनपति, अंजू, मुकेश, निर्मला ने भी सभा को सम्बोधित किया। वहां से जुलूस बना कर लघुसचिवालय पहुंची और ज्ञापन सौंपे।

यूनियन नेताओं ने कहा कि विभाग उनसे बंधुआ जैसा अनुचित बर्ताव करता है, रजिस्टर व फार्म भी खुद अपने पैसों से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। आंगनवाड़ी कर्मियों से भिन्न-भिन्न किस्म के कार्य कराये जाते हैं जिनका उनकी ड्यूटी से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकारी आदेश बता कर आंगनवाड़ी कर्मियों को दण्डित करने का भय दिखाया जाता है। यह सर्वथा अनुचित है। प्राय: इन कार्यों का मेहनताना भी नहीं दिया जाता या नाममात्र का दिया जाता है। कई बार तो रातोंरात ये कार्य करने के आदेश होते हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों से ऐसे कार्य न करवाये जाएं। प्रात: 8.45 से 2.45 बजे तक कार्य करने के बाद उन्हें अपना, अपने बच्चों व परिवार का जिम्मा निभाना होता है। यह उनकी गृहस्थी पर भी नाजायज दबाव है। यूनियन ने अपनी समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मियों को छोटे बच्चों को केन्द्र में 12.45 बजे तक बिठा कर रखने के निर्देश हैं। इतने छोटे बच्चों को इतनी देर तक बिठा कर रखना उनके लिए कठिन समस्या है। केन्द्रों की हालत अनुकूल नहीं है। लिहाजा 12 बजे तक उन्हें पूरक पोषाहार देकर इनकी छुट्टी कर देने की व्यवस्था की जाए, सीडीपीओ कार्यालय आने-जाने का किराया-भत्ता दिया जाए, पोषाहार का राशन रखने के लिए आंगनवाड़ी कर्मियों को टंकी/ड्राम/अन्य पात्र दिया जाए, फलैक्सी फण्ड का 1000 रुपया आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए आता है वह उनकी राय-मशवरे से खर्च किया जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मर्जी के खिलाफ बी.एल.ओ. की ड्यूटी ली जाती है जो सरासर गलत है। स्वेच्छा से बी. एल.ओ. का कार्य करने के बदले साल में मात्र 3000 रुपये दिये जाते हैं –ये बहुत कम हैं, कम से कम 12000 रुपये सालाना दिये जाएं। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि शौचालयों का सर्वे करवाने, शौचालयों की सूची बार-बार बनवाने, अनाथ बच्चों का सर्वे कराने, 18 साल से नीचे के लड़कों/लड़कियों, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बी.पी.एल.सूची बारे रिपोर्ट तैयार करने से छुटकारा दिलाया जाए। किलोई ब्लाक में पिछले कई महीनों का बकाया मानदेय भत्ता शीघ्र दिया जाने, हर माह की 7 तारीख तक उनके खाते में पैसे जमा किये जाने, आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया हर माह दिया जाने, विधवा पैंशन बन्द न करने, एसएमएस ग्रुप का भी मेहनताना दिया जाने, गैस सिलैण्डर की सब्सिडी आंगनवाड़ी के खाते में जमा कराई जाने, आंगनवाड़ी कर्मियों से 20 रजिस्टरों को भरने का जो कार्य कराया जाता है उसे सरल करने, अनावश्यक बोझ न डालने और रजिस्टर विभाग की तरफ से मुहैया कराने की मांग की।

छात्रों का तृतीय जिला सम्मेलन

ग्वालियर (म.प्र.) : सेमेस्टर प्रणाली, 8वीं तक बेरोकटोक पास प्रणाली, CBCS, ग्रेडिंग प्रणाली, प्रदेश के स्कूलों के निजीकरण के खिलाफ ग्वालियर जिला इकाई द्वारा तृतीय जिला सम्मेलन का आयोजन 22 अगस्त को किया गया। सम्मेलन की शुरूआत डी.एस.ओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कॉ. मुकेश सेमवाल द्वारा ध्वजारोहण के साथ की गई। इसके बाद क्रांतिकारी पार्टी एस.यू.सी.आई (कम्यूनिस्ट) के म.प्र. राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल, ग्वालियर जिला सचिव कॉ. सुनील गोपाल व डी.एस.ओ के अखिल भारतीय सचिव मंडल सदस्य कॉ. सचिन जैन ने शहीद वेदी पर पुष्पार्पण किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कॉ. मुकेश सेमवाल ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में लगातार किए जा रहे परिवर्तन व शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण की निन्दा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मुनष्य को सच के साथ खड़े रहने व गलत के खिलाफ लड़ना सिखाती है किन्तु वर्तमान शिक्षा छात्रों को एक मशीनी मानव में तब्दील कर छात्रों की नैतिक रीढ़ को ही कमजोर कर रही है। उन्होंने वैज्ञानिक व सही शिक्षा की मांग को लेकर आन्दोलन गठित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सम्मेलन में स्कूलों के निजीकरण व बेरोकटोक पास-प्रणाली को तुरंत वापस लेने की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। उत्तराखंड से आएं प्रतिनिधियों ने भी छात्र आन्दोलन का समर्थन किया। छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें क्रांतिकारी गीत, समूह नृत्य व माईम को दर्शकों ने बेहद सराहा।

सम्मेलन के प्रतिनिधि अधिवेशन में 200 व खुले अधिवेशन में 450 छात्रों व अभिभावकों ने शिरकत की। सम्मेलन में 33 सदस्यीय जिला कमेटी गठित हुई।

खराब फसल के मुआवजा की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन

अमरोहा (उ.प्र.) : 7 सितम्बर को मेहनतकश जन संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने जिला अधिकारी, अमरोहा के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर जिला अधिकारी, अमरोहा को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। जिला अधिकारी, अमरोहा के कार्यालय के समक्ष हुई विरोध सभा में गंभीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, सिद्धराज सिंह, नरेन्द्र सिंह, धर्मपाल सिंह, बलबीर सिंह, शिवचरण सिंह, वाहिद खां, अनीश खां, आदि अनेक किसान मौजूद थे। ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों को गन्ने की फसल का ब्याज सहित सम्पूर्ण भुगतान तुरन्त किया जाए, बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा तुरन्त दिया जाए, आन्दोलनकारी किसानों पर बनाये गये मुकदमें वापस लिए जाएं और सम्भल जिले की नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा जिले में शामिल किया जाए।

14 सितम्बर को संगठन के मुरादाबाद मण्डल के संयोजक गम्भीर सिंह के नेतृत्व में समिति ने जिलाधिकारी, संभल के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि बेमौसम बरसात से खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने और चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ने की फसल का भुगतान न किये जाने से किसान व बंटाईदार कर्जवान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अमरोहा व सम्भल जिलों के वर्तमान परिसीमन पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की और चीनी मिलों को अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में चालू करने और सम्भल जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। इस मौके पर गंभीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, सिद्धराज सिंह, नरेन्द्र सिंह, धर्मपाल सिंह, बलबीर सिंह, शिवचरण सिंह, वाहिद खां, अनीश खां, कल्लू सिंह, हरपाल सिंह, गंगासरण, मवाराम, वीर सिंह आदि मौजूद थे।

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly

शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता पर परोक्ष हमलों का प्रतिरोध करें

हिटलर ने एक बार कहा था कि यदि वह पाठ्य पुस्तकों पर नियंत्रण कर सके तो वह राजसत्ता पर भी नियंत्रण कर सकता है। उसका आशय यह था कि यदि शिक्षा के क्षेत्र को उसके फासीवादी प्रशासन के सीधे नियंत्रण में लाया जा सके तो देशवासियों के सोचने के ढंग को ही नियंत्रित करना, चिंतन प्रक्रिया को एक खास सांचे में ढालना (रेजिमेंट) करना, जनमानस को अंधविश्वास, कट्टरपन, अंधराष्ट्रवाद के रहस्यमय गर्त में धकेलना और इस प्रकार समाज के फासीवादीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना उसके लिए आसान हो जाता। वह सही कहता था। विज्ञान और वैज्ञानिक मनोभाव, धर्मनिरपेक्ष मूल्यबोध, तार्किक चिंतन प्रक्रिया को गढ़ना और मानवीय मूल्यों, नीति-नैतिकता और गुणवत्ता को पनपाना आधुनिक समय की किसी भी प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। इसी अर्थ में कहा जाता है कि एक देश का भाग्य उस देश के क्लास रूमों में ही संवारा जाता है। इसलिए, यदि शिक्षा को उसके सारतत्व से विहीन कर दिया जाये और मानव निर्माण के इसके उद्देश्य से भटका दिया जाये तो शासक जो लोगों के ज्ञानवान होने से इसलिए डरते हैं कि कहीं यह उनके दमनात्मक शासन के खिलाफ बगावत न भड़का दें, वे सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं कम से कम फिलहाल के लिए। इसीलिए शिक्षा पर उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। अब तो लगभग तमाम पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में फासीवाद सामान्य लक्षण बन चुका है। पूँजीवादी भारत भी इसका कोई अपवाद नहीं है। बल्कि बहुत से अन्य देशों के मुकाबले भारत में शिक्षा के हालात बदतर हैं।

अकादमिक स्वायत्तता निशाने पर है

पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में इस तरीके से बदलाव लाये जा रहे हैं कि यह और कुछ नहीं बल्कि तथ्यों का संग्रह मात्र बनकर रह जाये जो सत्य जानने की क्षमता प्रदान नहीं करता है। इसके साथ ही साथ शासक पूँजीपति वर्ग शिक्षा को जड़ वस्तु में तब्दील करने का षड़यंत्र रच रहे हैं जो पूँजीवादी बाजार के नियमों के अधीन हो। शिक्षा का व्यापक बाजारीकरण किया जा रहा है, फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी सहित विभिन्न तरीकों से करोड़ों उत्पीड़ित लोगों के लिये शिक्षा के दरवाजे बन्द किए जा रहे हैं, शिक्षा के भारतीकरण और आध्यात्मिकीकरण के नाम पर देश को मध्ययुगीन अंधकार युग में धकेला जा रहा है, शासक वर्ग की तरफ से उठाए जा रहे ऐसे ही अन्य घातक कदम शिक्षा के अंधकारमय परिदृश्य की पहचान बन गये हैं। साथ ही साथ अकादमिक स्वायत्तता को ध्वस्त करने के लिए खुल्लम-खुल्ला कदम उठाये जा रहे हैं। सत्ताधारी शिक्षा के क्षेत्र को सरकार और प्रशासन के दुमछल्ले में तब्दील करने के हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा तथा लोगों के जनवादी अधिकारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि यही खतरे में पड़ जाए तो ज्ञान का सच्चा अनुधावन और विस्तार निश्चित ही मार खायेगा। हमारे आजादी आन्दोलन के दौरान भी अकादमिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए भारतीय नवजागरण के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों द्वारा आवाज उठाई गई थी। फिर भी हाल के वर्षों में, पूरे देश में, विभिन्न सरकारों द्वारा किये जा रहे परोक्ष हमलों को हम देख रहे हैं-शब्दाडम्बरों की आड़ और बहानों के तहत हो या परोक्ष दबाव डालने के माध्यम से ही या यहां तक कि खुले और नग्न हस्तक्षेप के जरिये हो।

पश्चिम बंगाल में सीपीएम सरकार ने रास्ता दिखाया

अकेदमिक स्वायत्तता पर सबसे पहला और अति नग्न हमला पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती सीपीएम सरकार द्वारा 1970 के दशक के अंतिम दौर में किया गया था। इसे अंजाम दिया गया था शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों में राजनैतिक और सरकारी हस्तक्षेप के जरिये संस्थानों के मुखियाओं जैसे उपकुलपतियों के पद पर ताबेदार लोगों की नियुक्ति के रूप में और स्कूलों, कालेजों तथा उच्च शिक्षा के तमाम संस्थानों को चलाने के लिए जिम्मेदार गवर्निंग बॉडियों पर अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण कायम करके-ऐसा एक ट्रेण्ड जो समय बीतने के साथ सर्वव्यापक बन गया और विश्व विद्यालयों से शुरू होकर प्राइमरी लेवल स्कूलों तक पंहुच गया। असल में कोलकाता युनिवर्सिटी की स्वायत्तता में कटौती करने और यूनिवर्सिटी के क्रिया-कलापों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिये विधानसभा में वे एक विधेयक लाये थे। लेकिन इसे शिक्षा-प्रेमी जनवाद-पसन्द लोगों और विद्वानों की जाग्रत चेतना द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों के जाने माने शिक्षाविदों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, न्यायविदों, पत्रकारों और कलाकारों ने न केवल विरोध का स्वर बुलन्द किया बल्कि एक सरकार जो अपने आप को वामपंथी मार्क्सवादी कहती है, के ऐसे घातक कदम को रोकने के लिए सड़कों पर भी उतर आये। इसके बाद, सीपीएम सरकार की धारा का अनुसरण करते हुए, दोनों ही, केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने भी शासक पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ में शिक्षा सुधार के आडम्बरपूर्ण षड़यंत्र के हिस्से के रूप में अकादमिक स्वायत्तता को ध्वस्त करने की प्रक्रिया लागू करनी शुरू कर दी। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों पर न केवल सरकारों की बल्कि शासक पार्टियों की भी मजबूत पकड़ को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधार लाए गये हैं।

तृणमूल कांग्रेस सरकार और भी नग्न रूप से सीपीएम के पदचिन्हों पर चल रही है

इस मामले में भी पश्चिम बंगाल प्रमुखता से सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस जो एक समय विभिन्न शिक्षण संस्थानों पर पार्टी नियंत्रण कायम करने के लिए सीपीएम को खरी-खोटी सुनाती थी, स्पष्ट है कि लोग दिखावे और चुनावी लाभ बटोरने के लिए अब सत्ता मे आते ही सीपीएम के पदचिन्हों का अनुसरण कर रही है। यूनिवर्सिटियों और कालेजों की तो बात ही क्या राज्य में शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जिसमें पक्का टी.एम.सी. का आदमी या टी.एम.सी. वफादारों का एक ग्रुप संचालनकर्ता की भूमिका में न हो। यहां तक की विभिन्न शिक्षा निकायों जैसे प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड, सैकेंड्री एण्ड हायर एजुकेशन बोर्डों, ज्वाइंट एन्ट्रेंस एग्जामीनेशन काऊन्सिलों आदि सभी में ही टी.एम.सी. के लोग शिखर पर हैं। न केवल टी.एम.सी. नेतागण और मंत्रीगण या शिक्षा की कोई पृष्ठभूमि न रहते हुए भी शासक पार्टी के नुमाइंदे बल्कि कुख्यात अपराधियों और असमाजिक तत्वों को भी स्कूल-कॉलेजों की गवर्निंग बॉडियों का मुखिया बना दिया गया है। कौन अध्यापक होंगे से शुरू कर, कौन छात्र संघों को चलायेगा, किसको मिड-डे मील तैयार करने का, भवन निर्माण का, विभिन्न स्टेशनरी आइटम सप्लाई करने का ठेका मिलेगा इत्यादि-इत्यादि, सभी कुछ का इन अपराधियों को निरंकुश अधिकार दे दिया गया है, वे जो चाहे कर सकते हैं। यहां तक कि ये अपराधी ही तय करते हैं कि किसको पास किया जायेगा, परिक्षाओं के दौरान कौन निरीक्षक होंगे, जहां नकल करने की खुली छूट होगी और किस छात्र को कितने अंक दिये जायेंगे। स्कूल-कालेजों के अधिकारिकयों को शून्य बना दिया गया है और वे मूक दर्शक बनकर रह गये हैं।

लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अब हमारी पार्टी के साथ-साथ अन्य विपक्षी पार्टियों, प्रख्यात शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के जबरदस्त विराध को बेशर्मी से दरकिनार करते हुए टी.एम.सी. सरकार ने वेस्ट बंगाल स्टेट काऊन्सिल ऑफ हायर एजुकेशन बिल 2015 पास कर दिया है। बिल के जरिये हायर एजुकेशन काऊन्सिल के चेयरमैन के तौर पर (किसी जाने माने शिक्षाविद् की जगह) शिक्षामन्त्री की नियुक्ति को कानूनी मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा, इस बिल के प्रावधानों में, काऊन्सिल को कॉमन एन्ट्रेस टेस्ट संचालित करने का अधिकार भी दिया गया है, यदि कोई यूनिवर्सिटी इसके लिए ऐसा अनुरोध करती है। हैरानी की बात है कि स्वायत्त निकायों के नियंत्रण को इस तरह एक झटके में हड़प लेने को टी.एम.सी. शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जी ने जायज ठहराया है, यह तर्क सामने रखते हुए कि यह काऊन्सिल को और अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगा। इस मामले में गुजरात द्वारा, बाद में कर्नाटक और केरल के साथ-साथ महाराष्ट्र द्वारा पेश की गई मिसालों को दिखाते हुये भी उन्होंने इसे उचित ठहराया है।

सवाल पूछा जा सकता है, कांऊसिल को किसके प्रति और ज्यादा 'जिम्मेदार और जवाबदेह' बनाया गया है, शिक्षा के हित के प्रति या सरकार तथा शासक पार्टी के प्रति? इसका जवाब भी टी.एम.सी. शिक्षामन्त्री ने ही दे दिया है। पश्चिम बंगाल में हाल में हुए नगरपालिका चुनावों में की गई दहशतगर्दी और व्यापक धांधली के खिलाफ गत 30 अप्रैल को विपक्षी पार्टियों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। हमारी पार्टी ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। पूर्व में ऐसे अवसरों पर, यातायात व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका और बंद विरोधियों के बीच टकराव की संभावना के चलते आमतौर पर शिक्षण संस्थान परीक्षाओं को स्थगित कर दिया करते ताकि छात्रों का नुकसान न हो। लेकिन टी.एम.सी. ने बंद को विफल करने के अपने प्रयास में एक नोटिफिकेशन के जरिये आदेश जारी कर दिया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षायें उसी दिन होनी चाहियें। ऐसी एक अभूतपूर्व स्थिति ने विभिन्न परीक्षायें देने वाले लगभग 90 हजार यूनिवर्सिटी छात्रों को अनावश्यक अनिश्चितता और वेदना में धकेलते हुये मझधार में छोड़ दिया। जब मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि यदि बंद के दिन यूनिवर्सिटी को परीक्षायें कराने के लिए मजबूर किया जाता है तो सरकार का यह कदम अकादमिक मामलों में निर्लज्ज हस्तक्षेप है, शिक्षामन्त्री ने जोर देकर कहा कि निश्चित ही शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का उनका अधिकार है, क्योंकि अतत: वही तो हैं जो यूनिवर्सिटी टीचरों और स्टाफ को वेतनों का तमाम भुगतान करते हैं। अकादमिक स्वायत्तता के निर्लज्ज ध्वंस को जायज ठहराने के लिए इससे ज्यादा निरंकुशता और स्वेच्छाचार और क्या हो सकता है? शासक पूँजीपति वर्ग के चाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने की वजह से इतने दम्भी हो गये हैं कि वे कुछ भी बकवास या अंटसंट कह सकते हैं। क्या एक यूनिवर्सिटी और एक सरकार के बीच का संबंध मालिक और नौकर का है? क्या टीएमसी मन्त्री नहीं जानते हैं कि यूनिवर्सिटियों या आमतौर पर शिक्षण संस्थानों को सरकार जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है वह लोगों के पैसे से दी जाती है जिसे सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के रूप में लोगों से वसूला जाता है? क्या सरकार उस पैसे की मालिक है या सिर्फ एक ट्रस्टी? एक लोकतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त रूप में धन मुहैया कराने तक सीमित है। लेकिन रोजमर्रा का संचालन, पाठ्यक्रम निर्धारित करना परीक्षाओं और मूल्यांकन की पद्धति तय करना इत्यादि पूरी तरह शिक्षाविदों की सरपरस्ती में स्वायत्त जनवादी तौर से चुने गये निकायों का अधिकार क्षेत्र है। इन निकायों के क्रिया कलापों या फैसलों पर सरकार द्वारा की जाने वाली किसी किस्म की दखलअन्दाजी अकादमिक स्वायत्तता का उल्लंघन होता है। यह और कुछ नहीं बल्कि डकैतों का तर्क है कि शिक्षण संस्थानों के अकादमिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सरकार को अधिकार है क्योंकि यह इन्हें धन प्रदान करती है। यह घटना एक और उदाहरण पेश करती है कि कैसे टीएमसी सरकार शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता पर ताजे हमले कर रही है, जनवादी क्रियाकलापों का जो कुछ भी बचा-खुचा हुआ है उसे ध्वस्त कर रही है जो खुद शिक्षा के लिए हानिकारक है। यह घटना ही यह संकेत भी देती है कि आने वाली चीजों का सूरतेहाल क्या होने जा रहा है।

बीजेपी सरकार भी पीछे नहीं है

बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार भी शैक्षणिक संस्थानों पर अपनी पकड़ बनाने में पीछे नहीं है। गत जनवरी में, बिजनौर के सांसद और मुजफ्फरनगर साम्प्रदायिक दंगों के मामलों में एक अभियुक्त कुँवर भारतेन्द्रा को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 'कोर्ट' जो इस विख्यात शैक्षणिक संस्थान की सर्वोच्च नीति निर्धारक बॉड़ी है, में नामांकित किया गया। शासक पार्टी के ऐसे एक दागी आदमी जिसका साम्प्रदायिक मनोभाव भी सर्वविदित है को ज्ञान की ऐसी एक उत्तम सीट पर नामांकित करना नितांत अलोकतान्त्रिक और अन्यायपूर्ण है और अन्य बातों के अलावा यह यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता का उल्लंघन करने पर लक्षित है। इसी तरह, हाल ही में बीजेपी सरकार ने इसकी पत्रिका (जर्नल) की सलाहकार समिति को भंग कर दिया जो रोमिला थापर, और इरफान हबीब सहित विश्वभर के 21 प्रख्यात इतिहासकारों को लेकर बनी थी, जाहिर तौर पर इस घृणित उद्देश्य के साथ कि प्रमुख अकादमिक बॉडी से युक्तिसंगत इतिहासकारों को निकाल दिया जाये, क्योंकि

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉ. असित भट्टाचार्य का भाषण ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

कॉमरेड भट्टाचार्य ने कहा, इतिहास के विभिन्न युगों में समाज की ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करने के रास्ते विभिन्न व्यक्तियों का आविर्भाव हुआ है। कॉमरेड घोष का अभ्युत्थान भी इसी रास्ते हुआ है। समय की मांग को पूरा करते हुए कॉमरेड शिवदास घोष ने खुद ही खुद को इस तरह निर्मित करने का सघर्ष किया था। प्रत्येक व्यक्ति को खुद की भूमिका के सम्बंध में इसी तरह सोचने की जरूरत है। इतिहास में व्यक्ति की भमिका कहने से एक अति महत्वपूर्ण बात है। यही जो मानवतावादी ज्योति प्रसाद अग्रवाल का आह्वान–तैयार हो जाओ नौजवान! तुम्हें अग्नि स्नान करना होगा। भावना क्या है? तुमको ही उपयुक्त भूमिका निभानी होगी। महान स्टालिन ने कहा था हे क्रान्तिकारी! मत भूलो, क्रान्ति के इस झण्डे को बुलन्द रखने के लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सभी महापुरूषों ने व्यक्ति की यथार्थ भूमिका पर जोर दिया था। कार्ल मार्क्स से शुरू कर सभी मार्क्सवादी विश्व कम्युनिज़्म निर्मित करने और उसको मजबूत करने के सवाल पर सामूहिक ज्ञान को अपनाने और सामूहिक नेतृत्व को अपरिहार्य बता कर बार–बार जोर देते आए हैं। व्यक्ति की भूमिका पर अधिकाधिक जोर देते आए हैं। इस इण्डिविजुअल को मैन कह कर परिभाषित किया है। यह मैन कहने से सभी मनुष्यों को ही समझाया है। दृढ़ता के साथ कहा कि इस मैन को इस तरह तमाम व्यक्तिगत सोच से मुक्त होकर इस जगह पहुँचना होगा, जैसे कि श्रम होगा प्राईम वांट ऑफ लाइफ। सभी मुष्यों के समन्वय से यह मैन एक दिन इमर्ज करेगा इसी तरह एक अति उन्नत जाति का मनुष्य होकर, इसी तर एक स्वत:स्फूर्त चरित्र का अधिकारी होगा, जो व्यक्तिगत रूप से कहीं कुछ पाना नहीं चाहता, खुद का सब कुछ समाज को हाथ खाली कर के दे देना चाहता है। इस समझ का अधिकारी होने की अंतनिर्हित बात है, इसके माध्यम से समाज और व्यक्ति का एक साथ उन्नत होना।

आसाम की परिस्थिति के बारे में कुछ बोलने का अनुरोध आया है। आसाम की जनता की समस्याओं का दूसरे राज्यों की जनता की समस्याओं से कोई बुनियादी फर्क नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता की ज्वलंत समस्याएं भी यही है। पश्चिम बंगाल मे सीपीएम की 34 वर्ष की सरकार चली जाने पर क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सरकार में आने के बाद भी जीवन की समस्याओं में कोई बदलाव नहीं आया है। जनता ने जिस परिवर्तन की उम्मीद की थी वह नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता। यह क्रम चलता ही रहेगा जब तक क्रान्ति की चोट से शोषणमूलक इस राजसत्ता को उखाड़ फेंक करके देश में समाजवादी राजसत्ता कायम नहीं हो जाती है। असाम के मामले में भी यही बात लागू है। जनता खुले आसमान के नीचे मर रही है लेकिन एकमात्र हमारी पार्टी के सिवा जनता की सहायता करने वाला और कोई नहीं है। अत: जनता को भरोसा देना होगा कि संकट के समय हम उनके साथ खड़े हैं और हरदम साथ रहेंगे। इसीलिए पार्टी के हर सदस्य–समर्थक को इसी तरह तैयार करना होगा। जनता की समस्याओं को लेकर एक के बाद एक जुझारू जन–आन्दोलन संगठित करना होगा। आसाम में यह जो नागरिक पंजीकरण हो रहा है इससे लाखों लाख लोगों को परेशान किए जाने से लोगों की नींद हराम हो गई है। एन.आर.सी. (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न) के नवीनीकरण को केन्द्र करके इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है जो लगभग लटकती तलवार की तरह है। हम बार–बार कहते आ रहे हैं यह लाखों–लाख लोगों के जीवन के समतुल्य नागरिकता को छीन लेना एक जघन्य षड्यंत्र है। आप जानते हैं एन.आर.सी. के सवाल पर हमारा वक्तव्य सुनकर असहाय लोगों को एक सहारा मिल गया, आत्मविश्वास लौट आया। पत्र–पत्रिकाओं में चिट्ठी पत्रों के माध्यम से यह प्रकाशित हो रहा है। हमने क्या किया था? मार्क्सवाद–लेनिनवाद–कॉमरेड शिवदास घोष चिन्तन के आधार पर समस्या का विश्लेषण किया था। इसी से ही लोग चुम्बक की तरह आकर्षित हो रहे हैं। बराक वैली में इसका विरोध करने के लिए हजारों हजार लोग संगठित हो रहे हैं। धुबड़ी–ग्वालपाड़ा की तस्वीर भी ऐसी ही है। हम जितनी दूर तक आन्दोलन संगठित कर सके हैं उसका प्रभाव जनता को आन्दोलन में खींच ला रहा है। यह सब यही दर्शाता है कि लोगों को जागरूक बना देना संभव है। इसके लिए वह शक्ति अर्जित करनी होगी। सबसे पहले खुद को मृत्यु के भय से ऊपर उठाना होगा। जीवन को संघर्षशील रूप में ढालना होगा। तभी दुश्मन को पराजित किया जा सकेगा। अत: एन.आर.सी. के आक्रमण को रोकने के लिए सब तरह से तैयार होना होगा। राज्य में शक्तिशाली वामपंथी आन्दोलन के अभाव की वजह से उग्र क्षेत्रीयतावादी, साम्प्रदायिक शक्तियाँ इस समस्या को पैदा कर सकी हैं। असल कम्युनिस्ट आन्दोलन को शक्तिशाली कर पाने से ही इन समस्याओं का मुकाबला करना संभव है।

आप जानते हैं एक साईक्लोन जब आता है तब वह ध्वंस की तांडवलीला मचाता है। इस एन.आर.सी. को लागू करने का तमाशा भी एक सुविचारित साईक्लोन जैसा ही आक्रमण है। साईक्लोन जिस तरह ध्वंस का प्रतीक है। यह एन आर सी ऑपरेशन भी वही है। इससे क्षय क्षति एक तरह से होगी ही। लेकिन टूट जाने से काम नहीं चलेगा। एक अति अनुशासित सेना की तरह इसका मुकाबला करना होगा। इसी वजह से मृत्यु के भय से ऊपर उठना होगा। अन्याय को आधार कर निर्मित शक्ति, तर्क नहीं मानती है। उपयुक्त ताकत के साथ इसको रोकना होगा। लोगों के इस प्रकार घर में या बाहर में जमा विक्षोभ का जैसे तैसे प्रकटीकरण नहीं, विक्षिप्त आतंकवादी कोई भी काम नहीं, विशाल संगठित शक्ति निर्मित करनी होगी। जाति–धर्म–भाषा–वर्ण सभी कुछ से परे सभी सुबुद्धिसम्पन्न लोगों को आन्दोलन में शामिल कराना होगा। नागरिकता खो देना लोगों की मांग की न्यायसंगतता को उन्हें समझना होगा। कालक्रम में यही आन्दोलन जोरदार हो उठेगा, इसके माध्यम से नागरिकता को पुन: हासिल करना होगा। इस समय चाहे जो कुछ भी घटे, अत तक इस महा शक्तिशाली आन्दोलन के सामने अन्यायकारियों को सिर नीचा करना होगा। इसीलिए लेनिन की शिक्षा को दिमाग में रखते हुए उसको चारित्रिक दृढ़ता में परिणत करो, आक्रमण के खिलाफ डट कर खड़े हो जाओ।

शुरू में राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड चन्द्रलेखा दास और राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड अजहर हुसैन ने महान नेता के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए आसाम तथा उत्तर पूर्व भारत में एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) को शक्तिशाली करते हुए निर्मित करने का आह्वान किया।

●●●

शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता ...

(पृष्ठ 6 का शेष)

इतिहास के विकृतीकरण और तथाकथित भारतीयकरण के विचार के साथ सामंजस्य करते हुये कल्पना और मिथक को इतिहास के रूप में पेश करने और भगवाकरण के प्रयास में अपने घोर साम्प्रदायिक राजनैतिक–सांस्कृतिक ऐजेंडे को पुख्ता करने के लिए शासक आर.एस.एस.–बीजेपी जिस पर इतना गर्व कर रही है उसके खिलाफ अपनी आलोचना में ये इतिहासकार बहुत कटु रहे हैं। एक समय में बीजेपी मुखपत्र 'कमल संदेश' की सम्पादक मंडली का हिस्सा रहे और अपने निश्चित हिन्दू साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह के लिए मशहूर अम्बा चरण वशिष्ट को नेशनल काऊन्सिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (एन.सी.ई.आर.टी.) के प्रकाशन विभाग का सदस्य बना दिया गया। ऐसी नियुक्तियों के लिये स्थापित प्रक्रिया को ताक पर रख दिया गया। बीजेपी के आदमी के रूप में ज्ञात गजेन्द्र चौहान की पुणे के प्रतिष्ठित एफ.टी.आई.आई के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति ने सभी सरोकार रखने वालों को क्षुब्ध किया है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा आई.आई.टी. मद्रास के अम्बेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वहां भूमि अधिग्रहण बिल, कुछ राज्यों में गौमांस पर प्रतिबंध और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी बीजेपी–आर.आर.एस. की कुछ विनाशकारी जनविरोधी नीतियों की आलाचना की गई थी। यह घटना भी अकेडमिक चर्चा बहसों के क्षेत्र तक में विरोध की आावाज का जबरन गला घोंटने की वजह से अकेडमिक स्वायत्तता को ध्वस्त करने के दायरे में आती है। क्यों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मद्रास आई.आई.टी जैसे स्वायत्त संस्थानों के रोजमर्रा के क्रियाकलापों में दखल दिया जायेगा? सिर्फ इसलिए की किसी ने दावा किया है कि विशेष छात्र संगठन मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ 'नफरत' फैला रहा है। यहीं पर अंत नहीं है। बीजेपी सरकार अब ड्राफ्ट आई.आई.एम. बिल 2015 लायी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा कहा गया कि "इस कानून से पहले के प्रावधानों में दर्ज मौजूदा अधिकार को प्रभावित किये बिना, संस्थान (आई आई एम), इस कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए, नीतिगत सवालों पर ऐसे दिशा–निर्देशों से बंधे रहेंगे जिन्हें केन्दीय सरकार समय–समय पर इन्हें लिखित में दे सकती है..... इत्यादि। एक सवाल नीतिगत है या नहीं इस पर केन्द्रीय सरकार का फैसला अंतिम होगा" हालांकि बिल कहता है कि प्रत्येक आईआईएम का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स "मुख्य कार्यकारी निकाय" होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार को ऐसे अधिकार भी प्रदान करता है जिन्हें वह बोर्ड के फैसलों को रद्द करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यहीं पर बीजेपी और टी.एम.सी. एक थैली के चट्टे–बट्टे हैं। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही शासक पूँजीपति वर्ग के घातक वर्ग षड़यन्त्र को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस सड़न को रोकने के लिए शिक्षा–प्रेमी लोगों को सकारात्मक रूप से कार्यवाही करनी चाहिए

यही कारण है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर ऐसे राष्ट्र–व्यापी हमले के साथ–साथ प्रशासन के हाथों में अफसरशाही अधिकारों को केन्द्रीभूत करने के प्रयास जारी हैं। जिनका उद्देश्य है परिकल्पित शैक्षणिक नीतिगत–कदमों के लागू करने पर होने वाले किसी भी प्रकार के विरोध को खत्म किया जा सके, जिन्हें उच्च शिक्षा को इसकी व्याधियों से छूटकारा दिलाने के नाम पर और अन्य लोक–लुभावन नारों की आड़ में लागू किया जा रहा है, जो असल में उच्च शिक्षा को मात्र बाजार की बिकाऊ वस्तु में तब्दील कर डालने पर लक्षित हैं और गैर–वैज्ञानिक, गैर–ऐतिहासिक, विकृत विचारों को प्रसारित करने का जरिया हैं, जो ज्ञानवर्धन की बजाये छात्रों को बौद्धिक रूप से पंगु बना देंगे। सुस्पष्ट रूप से, तमाम शासक पार्टियाँ शिक्षा क्षेत्र को उसी सांचे में ढालने पर आमादा हैं जिसका रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत पहले ये कहते हुए विरोध किया था कि "शिक्षा को सरकार के दुमछल्लों में तब्दील कर डालने के ऐसे प्रयास शासकों के घृणित राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति पर लक्षित हैं।" जबकि इस संबंध में प्रत्येक शासक पार्टी का अपना खुद का ऐजेंडा है, फिर भी याद रखना चाहिये कि, जैसा पहले बताया गया है, यह सब शिक्षा को तबाह करने के पूँजीपति वर्ग के व्यापक षड़यंत्र का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए आज कोई भी राजनैतिक पार्टी, चाहे उसके झण्डे का रंग कैसा भी हो, जो पूँजीपति की सेवा में लगी हैं इस रास्ते पर चलने के लिए बाध्य है। क्या जनवाद पसन्द लोग इसे निर्विरोध होने देंगे? क्या उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि यह सिर्फ शिक्षा तक सीमित मुद्दा नहीं रह गया है, पूरे राष्ट्र के जीवन के लिए इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे, विशेषकर बेरहम पूँजीवादी शोषण की चक्की में पिस रहे उत्पीड़ित और दमित लोगों के लिए। क्या उन्हें गहराई से नहीं सोचना चाहिये कि यदि समय रहते इस वर्ग षड़यंत्र को नहीं रोका गया तो क्या अंजाम होगा? क्या उन्हें स्वायत्तता पर ऐसे विनाशकारी हमलों और रेजिमेंटेशन के लिए उठाये जा रहे कदमों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध निर्मित करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? यदि जीवन के सभी तबकों के शिक्षा–प्रेमी, जनवाद पसंद लोग एक साथ आ जायें और इस वर्ग षड़यंत्र को विफल करने के लिए एकजुट हो जायें और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चाओं और बहसों का एक तूफान खड़ा कर दें तो अंतत: इससे एक जबरदस्त विपरीत धारा पैदा की जा सकती है और यह एक सशक्त संगठित शिक्षा बचाओ आन्दोलन में तब्दील हो सकता है, जो एकमात्र उपाय है शिक्षा और अकादमिक स्वायत्तता पर इस घृणित हमले को रोकने का। ●

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 20 Sept, 2015

सर्वहारा दृष्टिकोण

22 सितम्बर, 2015

गीता, रामायण, महाभारत के उपदेशों के साथ-साथ आध्यात्मिक ग्रंथों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने के

बीजेपी सरकार के घोर गैरजनवादी, शिक्षा-विरोधी प्रस्ताव का एसयूसीआई(सी) ने किया जोरदार विरोध

13 सितम्बर को जारी बयान में एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने कहा :

रामायण, महाभारत और गीता के उपदेशों और दूसरे तमाम आध्यात्मिक मूल्यों को स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार का फैसला अत्यंत आपत्तिजनक है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यह एक अच्छी तरह सोचा-समझा कदम है जो शिक्षा के साम्प्रदायीकरण और भगवाकरण के अनिष्टकारी षड्यंत्र से मेल खाता है। जो भी थोड़ी-बहुत धर्मनिरपेक्षता बची हुई है उसे भी यह अपने बहाव में बहा ले जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रमों में मिथक और धर्म को शामिल करने का यह कदम साफ तौर पर धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, जनवादी, सर्वजनीन शिक्षा की अवधारणा के खिलाफ जाता है। भारतीय नवजागरण काल के मनीषियों द्वारा धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, जनवादी, सर्वजनीन शिक्षा की इस अवधारणा का पुरजोर समर्थन किया गया था और सभी सही सोच रखने वाले जनवाद-पसंद शिक्षाविद, विद्वान और बुद्धिजीवी मजबूती के साथ इसका आज भी समर्थन करते हैं।

यह स्पष्ट है कि 'सांस्कृतिक प्रदूषण' से छुटकारा दिलाने और युवा मनों में 'मूल्यों को पनपाने' के नाम पर तार्किक चिंतन प्रक्रिया को कुंद करने, धर्मजागरण और पुराने दकियानूसी विचारों को रोपित करने और अंधविश्वास की रहस्यवादी गली में छात्रों के मानस को प्रवृत्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नेकनीयत रखने वाले नागरिकों, अध्यापकों, छात्रों, प्रोफेसरों, प्रिन्सीपलों, उपकुलपतियों, अभिभावकों, शिक्षण से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ-साथ मेहनतकश अवाम के तमाम तबकों से हम आह्वान करते हैं कि शिक्षा पर इस हमले को रोकने और जोरदार आन्दोलन गठित करने के लिए आगे आयें ताकि इस अनिष्टकारी प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके

माओ त्से-तुंग की 39वीं बरसी पर स्मृति सभा का आयोजन

रोहतक(हरियाणा) : विश्व सर्वहारा के महान नेता, शिक्षक एवं चीन की क्रान्ति के रचयिता कॉमरेड माओ त्से-तंग की 39वीं बरसी पर स्थानीय छोटूराम पार्क में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की ओर से एक स्मृति सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं ने माओ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धांजली दी और उनके जीवन संघर्ष और शिक्षाओं को याद किया।

रोहतक में सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

स्मृति सभा के मुख्य वक्ता थे पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य एवं राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड सत्यवान। माओ त्से-तुंग के जीवन संघर्ष और शिक्षाओं पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि आज जब विश्व साम्राज्यवाद-पूंजीवाद और प्रतिक्रियावादी ताकतें देश-देश में साम्यवादी आन्दोलन, मुक्ति-संघर्ष, प्रगति व जनतंत्र की लड़ाई पर जोरशोर से हमले कर रही हैं और विश्व साम्यवादी आन्दोलन के महान पथप्रदर्शकों की गौरवमय भावमूर्ति पर कालिख पोतने के कुत्सित अभियान में लिप्त हैं, ऐसे में महान माओ त्से-तुंग व उनकी शिक्षाओं को याद करना और भी जरूरी हो गया है। समाजवाद को लगे धक्के से उबरने और विश्व साम्यवादी आन्दोलन को सही रास्ते पर लाने में माओ की शिक्षाएं संशोधनवाद के खिलाफ लड़ाई में मार्गदर्शक भूमिका निभाती हैं। माओ ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को चीन की विशेष परिस्थिति में विशेषीकृत, समृद्ध और उन्नत किया। वे दुनिया के क्रान्तिकारियों के लिए अमूल्य ज्ञान भण्डार छोड़ गये हैं। उन्होंने 'एशिया के बीमार मुल्क' कहे जाने वाले चीन को सामंतों और साम्राज्यवादियों की दासता से मुक्त कराया और शोषणहीन व्यवस्था समाजवाद कायम किया। परन्तु भारत में उनकी शिक्षाओं की अवहेलना करके नक्सल व माओवादी कहे जाने वाले लोगों व दलों ने माओ के विचारों को गलत पेश करके न केवल माओ की प्रतिष्ठा को बट्टा लगाया है, बल्कि भारत की क्रान्ति को भी बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है।

सभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड अनूप सिंह मातनहेल ने की। राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड रामफल और ईश्वर सिंह राठी ने भी बात रखी।

भारत – अमेरिकी सैन्य गठजोड़ का एसयूसीआई(सी) ने किया पुरजोर विरोध

हाल ही के नये भारत-अमेरिकी सैन्य समझौते पर एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 16 सितम्बर को जारी बयान में कहा :

यह खबर है कि अमेरिका ने अपने जूनियर साम्राज्यवादी पार्टनर भारत के साथ अपने सैन्य सम्बन्ध और भी मजबूत बनाने के लिए एक 'इण्डिया रेपिड एक्शन सैल' हाल ही में गठित किया है, अत्याधुनिक हथियारों के संयुक्त उत्पादन की योजना के तहत जिसका उद्देश्य ''दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा'' को मजबूत करना है इसका असल मायने है मध्य पूर्व सहित एशिया पर अमेरिकी सैन्य आधिपत्य को आगे बढ़ाना। यह साफ तौर से दर्शाता है कि भारत एक उभरती हुई साम्राज्यवादी शक्ति होने के नाते अमेरिकी साम्राज्यवादी षड्यंत्रों का सक्रिय हिस्सेदार बन गया है। यह न केवल भारतीय अवाम के बल्कि पूरे जोन के अवामों के लिए गहरी चिंता का विषय है।

यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकारी घरानों की मुनाफे की भूख मिटाने के लिए बीजेपी-नीत केन्द्रीय सरकार अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए भोजन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण सम्बन्धी अन्य मदों का बजट घटाकर रक्षा बजट लगातार बढ़ाती जा रही है।

युद्ध के सौदागर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के साथ भारत के बढ़ते सैन्य गठजोड़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं और इस अनिष्टकर षड्यंत्र के साथ-साथ मिलिटरी बजट के लिए जनता के धन के बढ़ते आबंटन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का हम लोगों से आह्वान करते हैं।

मेडिकल सर्विस सेण्टर ने लगाये स्वास्थ्य जागरूकता कैम्प

दिल्ली : अगस्त और सितम्बर महीने में भारत के राजधानी शहर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया। यह भारत के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की झलक पेश करता है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बढ़चढ कर डींग हांकते है कि देश प्रगति पर है। हालांकि डेंगू से मौत के बहुत से मामले दर्ज ही नहीं होते हैं या नजरअंदाज कर दिये जाते हैं फिर भी सरकारी रिपोर्ट दिखा रही हैं कि डेंगू से 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अब तक दर्ज मामले 2000 से ऊपर हैं।

मेडिकल सर्विस सेण्टर की दिल्ली यूनिट ने 12 सितम्बर को भलस्वा में और 16 सितम्बर को मुकुन्दपुर में ''डेंगू से बचाव के उपाय'' बारे स्वास्थ्य जागरूकता कैम्प लगाये। भलस्वा में चर्चा का संचालन मेडिकल सर्विस सेण्टर के सह सचिव डा. जे.एन. मुर्मु ने किया। मुकुन्दपुर में चर्चा का संचालन एम. चौरसिया और मेडिकल सर्विस सेण्टर के सह सचिव डा. जे.एन. मुर्मु ने किया। दोनों जगह कैम्पों में लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई ओर सक्रिय भागीदारी की। रोग निदान से डेंगू के एक मरीज का पता चला जिसे उपयुक्त बचाव उपाय बरतने की सलाह दी गई।

हरियाणा पंचायत चुनाव लड़ने की शर्तों बारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये स्टे से हुई है लोगों के मौलिक अधिकारों की बहाली –एसयूसीआई(सी)

रोहतक (हरियाणा) : एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान ने 17 सितम्बर को जारी एक बयान में खुशी प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव में शिक्षा और दूसरी शर्तों वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे देने से प्रदेश की जनता को राहत मिली है। सरकार ने जनता के बहुसंख्यक हिस्से को पंचायत चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था। हरियाणा सरकार द्वारा पहले जारी किये गये अध्यादेश पर हाई कोर्ट ने दे स्टे दिया था लेकिन सरकार द्वारा हरियाणा पंचायत राज (संशोधन)कानून 2015 विधानसभा में पास कर दिया गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

जहां भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र होने के लिए 10वीं, 8वीं, 5वीं पास शिक्षित होने, पक्का शौचालय होने, बैंक के कर्ज और बिजली बिल का भुगतान करने में डिफाल्टर न होने जैसी शर्तें लगा दी थी। कांग्रेस ने महज किंतु-परंतु कहने के अलावा कोई नीतिगत विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा कर प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों को राहत पहुंचाई है। इस फैसले से लोगों के मौलिक जनतांत्रिक अधिकारों की बहाली हुई है।

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631